भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2261
उत्तर देने की तारीख 12 मार्च, 2026

पार्सल और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में पहल

2261. श्री अमर पाल मौर्य :
डा. कविता पाटीदार :
श्री मिथलेश कुमार :
श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा :
श्री मिलिंद मुरली देवरा :
श्री मयंककुमार नायक :
श्री मनन कुमार मिश्र :
डा. भागवत कराड़ :
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े :
श्री चुन्नीलाल गरासिया :
श्री लहर सिंह सिरोया :
श्री एस. सेल्वागनबेथी :
श्री बाबू राम निषाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग द्वारा पार्सल और ई-कॉमर्स क्षेत्र (संभार-तंत्र) में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए तकनीकी उन्नयन, संभार-तंत्र आधुनिकीकरण और घरेलू एवं वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों/कंपनियों के साथ किए गए समझौते/साझेदारियों सहित की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पार्सल यातायात और संभार-तंत्र सेवाओं में दर्ज की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है तथा बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं;

(ग) क्या विभाग ने राजस्व सृजन और परिचालन दक्षता पर इन पहलों के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो वित्तीय प्रदर्शन संकेतकों और भविष्य की विस्तार कार्यनीति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) डाक विभाग ने भारतीय डाक को प्रमुख सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से अपने पार्सल और ई-कामर्स सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की है। इन मुख्य पहलों में, देशभर में मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से गति, विश्वसनीयता और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पार्सल प्रोसेसिंग और डिलीवरी व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाना शामिल है। उन्नत डाक प्रौद्योगिकी (एटीपी) परियोजना 2.0 के तहत, रियल टाइम ट्रैकिंग अपडेट, ओटीपी आधारित डिलीवरी, और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्मों तथा अन्य ग्राहकों को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटेरफेस (एपीआई) के साथ एकीकरण की शुरुआत की गई है। मेल एवं पार्सल ऑप्टिमाइजेशन परियोजना (एमपीओपी), ऑटोमेशन, मानकीकृत कार्यप्रवाह, और पार्सल सॉर्टर्स और रियल टाइम ट्रैकिंग प्रणाली जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से एंड-टु-एंड ऑप्टिमाइजेशन को सक्षम किया गया है।

विभाग ने प्रमुख ई-कामर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ साझेदारी की है और यह एमएसएमई मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी मंत्रालयों को पार्सल डिलीवरी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई, शिल्पियों, स्वयं सहायता समूहों, और छोटे-छोटे कारोबारों के निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता के लिए डाक निर्यात केंद्रों (डीएनके) की स्थापना की गई है। डाक विभाग ने अमेजन, शिपरॉकेट, डीकैथलॉन, और डीटीडीसी जैसी कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारियां की हैं, और यह ओएनडीसी प्लैटफ़ॉर्म से जुड़ा हुआ है।

(ख) विभाग ने हाल के वर्षों में पार्सल ट्रैफिक में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है, यह रणनीतिक सुधारों और ई-कॉमर्स क्षेत्र के विस्तार के कारण संभव हुआ है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	**घरेलू पार्सल ट्रैफिक (लाखों में)**
2022-23	431.52
2023-24	578.42
2024-25	712.01

विभाग ने कार्यप्रवाह को री-डिज़ाइन करने, प्रचालन क्षमता में सुधार करने, प्रचालन नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने, और पार्सल तथा ई-कॉमर्स खेपों के सुरक्षित तथा समय पर पारेषण के लिए अखिल भारतीय सड़क परिवहन नेटवर्क (एआईआरटीएन) शुरू करने के लिए बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) भी शुरू किया है।

(ग) एवं (घ) जी हां, एमपीओपी, जो प्रचालन सुधारों और अवसंरचना नियोजन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है, के तहत, विस्तृत लेन-वाइज़ वॉल्यूम मैपिंग, क्षमता पूर्वानुमान, और अवसंरचना अंतर मूल्यांकन किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेश डाटा-चालित और किफायती हों।

सभी प्रमुख क्षेत्रों में प्रचालन क्षमता में सुधार हुआ है। अभी, 145 शहरों में 234 नोडल डिलीवरी केंद्र हैं, जहां प्रतिदिन की पार्सल डिलीवरी का लगभग 30% कार्य यांत्रिक व्हीकल्स द्वारा हैंडल किया जाता है। आठ सेमी-ऑटोमेटेड छटांई प्रणाली हैं, जिनमें से प्रत्येक की प्रति घंटे 2,500 तक पार्सल प्रोसेस करने की क्षमता है, ताकि मैन्युअल हैंडलिंग और त्रुटियों को कम किया जा सके। एआईआरटीएन के अंतर्गत आने वाले 88 राष्ट्रीय मार्गों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 62,000 किलोमीटर की दूरी कवर की जाती है।

इन उपायों से पार्सल क्षेत्र में विभाग के वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पार्सल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 36.5% (जनवरी, 2026 तक) तक की वृद्धि हुई है।

*****